RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-09
September-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

# अशांत अफगानिस्तान में शांति का विकल्प

[1]डॉ श्याम मोहन अग्रवाल; [2]डॉ. मोहन लाल जाखड़

[1]एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
[2]शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

**ARTICLE DETAILS**

**Article History**
*Published Online:* 16 Sep 2019

**Keywords**
ग्रेट गेम, महाशक्तियाँ, तालिबान रणनीतिक सहभागिता समझौता, 2+2 वार्ता, गठबंधन सेनाएं, समावेशी विकास, पुनर्निर्माण, प्रायोजित आतंकवाद, नृ–जातीय समूह।

**ABSTRACT**

*अफगानिस्तान में शांति व स्थायित्व न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु सम्पूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका की सैन्य वापसी और उसके बाद उपजे हालातों निपटने के लिए अफगान सुरक्षा बलों की कमजोर रणनीति इत्यादि अनेक कारण है जो अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के प्रयासों को अवरोध करते है। ऐसे में भारत के द्वारा पिछले एक दशक से किए गये विकास कार्यों पर भी विपरीत असर पड सकता है। इससे अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के प्रयासों को झटका लग सकता है। ऐसे में अमेरिका को अपने सैन्य वापसी और सैन्य कटौती के प्रस्तावों को नामंजूर करना होगा और अफगानिस्तान के लिए दीर्घकालीन रणनीत बनाते हुए अफगान सरकार को अधिक मजबूत करने के साथ–साथ वहाँ के सुरक्षा बलो और कानून व्यवस्था में सुधार करना भी आवश्यक है।*

अफगानिस्तान में दशकों से यह जंग चल रही है इसमें समय के साथ उतार–चढाव आते रहे है लेकिन यह जंग खत्म नही हुई है। उसका एक विस्तृत इतिहास रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण प्रमुख रूप से उसकी भौगोलिक अवस्थिति और वहाँ की नृजातीय संरचना है। जो अफगानिस्तान की शांति के लिए हमेशा खतरा बनकर उभरे और उसका परिणाम आज भी अफगानिस्तान की जनता झेल रही है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन कब्जा नहीं कर पाया बीसवीं शताब्दी में सोवियत संघ के पतन का कारण बना और अब 21वीं सदी में अगर यू.एस. का वर्चस्व दुनिया में टूट रहा है तो पुनः एक कारण अफगानिस्तान बनने वाला है। ऐसे में अफगानिस्तान न केवल भारत और दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सम्पूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है अगर विश्व में शांति स्थापित करनी है तो अफगानिस्तान में शांति और समृद्धि का होना जरूरी है इसलिए सबसे पहले अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने का कार्य करना है लेकिन हाल ही की घटनाओं पर प्रकाश डाले तो शांति की संभावना हमें अफगानिस्तान में दूर तक नहीं दिखाई देती है। क्योंकि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में तालिबान–विरोधी नेता अहमद शाह मसूद की मौत की 17वीं बरसी पर तालिबान की और से किए गए अलग–अलग हमलों में से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है पिछले कुछ महिनों में जहाँ तालिबान ने अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में हमले तेज कर दिए हैं, वहीं गनी सरकार अभी आंतरिक समस्याओं का ही सामना कर रही है, बीते दिनों अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके डेप्युटी ने सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा दिया था। अमेरिका पिछले एक साल से तालिबान पर सैन्य दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे शांति समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन यह नीति अधिक कारगर होती नहीं दिख रही। तालिबान के हमलों में हताहतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। काबुल और जलालाबाद जैसे प्रमुख शहरों पर आतंकी हमले बढ़ गए है। अफगानिस्तान में बढते संघर्ष और हमलवार होते तालिबान की पृष्ठभूमि के बीच भारत की कोशिश है कि अफगानिस्तान सरकार को इस बात पर राजी किया जाए कि वह आंतरिक कलह को खत्म करे और तालिबान पर ध्यान दे।

अमेरिका द्वारा लगातार अफगानिस्तान में बदलती रणनीति की वजह से तालिबान पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाया। अमेरिका का तालिबान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण न रहकर पिछले 2–4 सालों से संदेहास्पद दृष्टिकोण रहा है कभी वह वार्ता के तालिबान के साथ तैयार होता है, कभी कोई ऐसी घटना या अमेरिकी सैनिकों पर हमला हो जाता है तो वार्ता प्रक्रिया को रोक देता है अर्थात् अमेरिका की अफगान रणनीति फेल होती नजर आ रही तालिबान से वार्ता या लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की अफगान नीति में काफी अस्थिरता और अनिश्चितता है। वे कभी तालिबान से लड़ने के लिए हवाई हमला करने के लिए बोलते है तो कभी जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए तो कभी तालिबान के साथ बातचीत कर अफगान समस्या का समाधान करने के लिए बयान देते है। ऐसे में यह देखना होगा कि अफगान समस्या के प्रति अमेरिका कितना गंभीर है और वास्तव में वह इस समस्या से निपटने के लिए कितना व्यवहारिक कदम उठाने के लिए तैयार है। जबकि अफगानिस्तान की बुनियादी समस्या है पाकिस्तान, पाकिस्तान का हस्तक्षेप अफगानिस्तान के राष्ट्रीय जीवन में तालिबान के

RRIJM 2015, All Rights Reserved

जरिए हैं, जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा तब तक अफगानिस्तान में शांति बहाली जैसे मुद्दों पर बात करना बेमानी होगा। क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि अफगानिस्तान में फैला तालिबान कोई बाहरी समस्या नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान प्रायोजित तालिबान है जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में अस्थिरता पैदा कर अमेरिका से अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करना है। इस मकसद को अमेरिका को समझना होगा और आतंकवाद के नाम पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को बंद करना होगा जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और वह फिर आतंकवाद को पोषित स्थिति कमजोर होगी और वह फिर आतंकवाद को पोषित करने से वंचित रह जायेगा। इसलिए अमेरिका को अगर अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व को खत्म करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को नियंत्रित करना होगा इसके लिए आर्थिक व कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को नियंत्रित करके तालिबान को वार्ता के लिए तैयार करना जिससे उनके द्वारा मूल समस्याओं को जाना जा सके जब तक अमेरिका तालिबान से प्रत्यक्ष बातचीत नहीं करता तब तक पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त नहीं करवा सकते है। दूसरी तरफ अफगान सरकार को भी तालिबान के साथ वार्ता प्रक्रिया करनी चाहिए क्योंकि मूलतः तालिबान एक कबिलाई समाज है जो विभिन्न नृजातीय गुटों में बंटा है और वे अफगानिस्तान के स्थायी निवासी है इसलिए इनकी पहचान करना भी मुश्किल है कि कौन अफगान नागरिक है और कौन तालिबानी है। ऐसे में इन नृजातीय समूहों की बातें अफगान सरकार को सुननी चाहिए और वार्ता के लिए एक मंच पर आना चाहिए। इसमें अमेरिका और अन्य देशों के सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है। जब से अफगानिस्तान में अमेरिका ने प्रवेश किया है तब से पूर्णतः तालिबान की गतिविधियाँ कभी खत्म नहीं हुए है। ऐसे में अमेरिका को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा क्योंकि 2001 में अमेरिका का अफगानिस्तान में प्रवेश करने का उद्देश्य अलकायदा को खत्म करना था, अलकायदा को तो काफी हद तक खत्म कर भी दिया इसमें पाकिस्तान ने भी उसमें मदद की और इस मदद के लिए पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन उसके बाद तालिबान को छूट दी क्योंकि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका अलकायदा पर अटैक किया और काबूल में 2004 तक तालिबान सत्ता पर काबिज था इस दौरान 2001 के बाद व 2004 तक के समय अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान के समर्थन से अपनी गहरी बैठ बना चुका था। इसके बाद वहाँ वैसी समस्या खडी हो गई कि जब तक पाकिस्तान पर जोर नहीं डाले अमेरिका तब तक इसका समाधान निकट भविष्य में होता नहीं दिखाई देता है। अमेरिका का प्राथमिक उद्देश्य अलकायदा था उस पर तो उसने सफलता प्राप्त कर ली तालिबान पर सफलता पाने के लिए वो कदम उठाने को तैयार नहीं है जो पाकिस्तान पर इतना दबाव डाले कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं हो और वह तालिबान से अपने रिश्तों में दूसरी बनाये यह अमेरिका करने को तैयार नहीं। दूरी तरफ अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय समस्या है जो अफगानिस्तान की सरकार है। अफगानिस्तान की बुनियादी समस्या है वहाँ की नृजातीय समस्या है जब तक इस कबिलाई समाज का कोई एक सांगठनिक लीडर उत्पन्न नहीं होता है तब तक एक पैन अफगान का निर्माण हो वहाँ के सूरते हालात में कोई बदलाव नहीं आऐगा एवं बाहरी हस्तक्षेप से समस्या और गंभीर बढेगी और अफगानिस्तान शांति के बजाय अशांति के दलदल में फंसता चला जाऐगा। ऐसे में हमें एक ऐसे अफगानिस्तान की जो कई दशकों से बाहरी हस्तक्षेपों की आग में झुलस रहा है उसको बचाना होना चाहिए। प्रत्येक देश का कूटनीतिक उद्देश्य अलग–अलग होता है अमेरिका अफगानिस्तान में अपने राजनीतिक एवं सामरिक हितों को अलग तरह से देखता है पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित अलग है भारत के राष्ट्रीय हित अलग है वहीं अफगानिस्तान का इन सबके प्रति रवैया अलग–अलग है। ऐसे में अमेरिका को अपनी अफगान नीति के क्रियान्वयन में फूंक–फूंक कर कदम उठाना चाहिए उसका एक–एक निर्णय अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। तालिबान के साथ वार्ता के लिए ठोस रणनीति के साथ आगे बढना चाहिए क्योंकि तालिबान का प्रभुत्व पाकिस्तान के चलते अधिक है ऐसे में अमेरिका को अपने हितों को अपने निजी हितों से ऊपर उठकर पाकिस्तान पर दबाव डालकर तालिबान पर प्रभावी अंकुश और शांति वार्ता की मेज पर लाना होना चाहिए ना कि उसे एक ऐसे दलदल में छोड़कर अपने सैनिकों को वापिस निकालकर अपने को यहाँ से भाग जाने में। अमेरिका खासकर ट्रंप सरकार के आने के बाद अफगानिस्तान के प्रति उनका ढुलमुल रवैया रहा जिसका परिणाम अफगानिस्तान में इन्सरजेंसी की घटनाऐं काफी बढी है। ऐसे में अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस लौटने के निर्णय को बदलना होगा नहीं तो पिछले दो दशकों से किये गये प्रयासों पर पानी फेरने के समान होगा और एक जीती हुई लड़ाई हार जाएंगे। जिस अफगानिस्तान को अमेरिका ने सुरक्षा व्यवस्था देकर और भारत ने आर्थिक–सामाजिक पुनर्निर्माण से खडा किया था उस पर वापिस तालिबान का शासन स्थापित होगा जो दोनों देशों के हितों के विरूद्ध होगा।

वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की बढती हुई शक्ति है इस वक्त उतर और उत्तर–पश्चिम में भी तालिबान का प्रभुत्व बढता जा रहा है इस क्षेत्र में तालिबान अपने नियंत्रण को अधिक मजबूत कर रहा है। अब यह समस्या इतनी बढ गई है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रीय एकता वाली सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह् लगने लगे है। दूसरी और अमेरिका की नीति भी असफल होती नजर आ रही है। ट्रंप प्रशासन अफगान की नई नीति पर बल देते हुए कहा था कि समय के ऊपर बल नहीं देते हुए हम स्थानीय आवश्यकता के आधार पर हम अपनी सैन्य क्षमता को बढाऐंगे और सैन्य

RRIJM 2015, All Rights Reserved 

ताकत के साथ–साथ हवाई शक्ति का प्रयोग करेंगे जहाँ–जहाँ जरूरत होगी। इसका प्रभाव यह होता है कि जहाँ–जहाँ शक्ति प्रयोग होता है वहाँ–वहाँ तालिबान पिछे हट जाता है लेकिन फिर बाद में अमेरिका सेना के पीछे लौटते ही वापिस आ जाते है। ऐसे में इस समस्या से निपटना अमेरिका के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। अब इससे निपटने के लिए अमेरिका तालिबान के साथ वार्ता के लिए तैयार हुआ है। पहले खुफिया माध्यमों अर्थात् Back Chanal Diplomacy के माध्यम से तालिबान के नेताओं से वार्ता के लिए प्रयास किया, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से खुले तौर से बातचीत के लिए तैयार हो रहा है और ऐसे में पहले दोहा में वार्ता और फिर काबुल में ऐसे दौर की वार्ता हुई। तालिबान वार्ता के लिए पहले से अधिक तत्पर नजर आता है। लेकिन उनकी विचारधारा में वार्ता का औचित्य तो होता नहीं वो तो कैसी भी उनके साथ वार्ता के लिए रूके रहना है जब तक उनकी व्यवस्था सुदृढ़ न हो जाए और राष्ट्रीय एकता सरकार गिए जाए और नए चुनाव होने वाले है तब तक वे अपने आप को रोके रखना चाहते है। ऐसे हालात में तालिबान को अफगानिस्तान में नियंत्रित करना है तो अमेरिका को पाकिस्तान के माध्यम से ही होकर आना पडेगा ऐसे में सीधे बातचीत की बातें नामुमकिन सी लग रही है। वहीं दूसरी और अमेरिका की अफगानिस्तान में एक सुदृढ़ रणनीति का भी अभाव रहा पहले कहा कि हम तालिबान के साथ वार्ता नहीं करेंगे और अब उस पर वार्ता के लिए दबाव डाला जा रहा है और वार्ता के संकेत भी मिल रहे है और अभी हाल ही में जुलाई माह में दोहा की राजधानी कतर में तालिबान और अफगान सरकार के साथ वार्ता हुई हैं इससे स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एक सफल रणनीति का अभाव देखा जा सकता है। अमेरिकी विदेशी नीति में जिसका लाभ पाकिस्तान उठा रहा है और तालिबान के माध्यम से वह अफगानिस्तान की राष्ट्रीय एकता सरकार को कमजोर करने और अशांति पैदा करके राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है ऐसे हालातों में अमेरिका को वहाँ से सैनिकों को हटा लेना एक गंभीर चिंता का विषय होगा। 2014 के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियाँ एकाएक तेज होती जा रही है और उनका प्रभाव भी बढ रहा है। इसके पीछे के कारणों में हम तीन चार समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे है।

**सुरक्षा की स्थिति** पिछले दस साल से सुरक्षा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। 2018 में पिछले 10 साल से अधिक घटनाऐं ज्यादा बढ़ी है। जो एक चिंता का विषय है। **राजनीतिक समस्या** का भी ऐसा कोई समाधान नहीं निकला जो अफगानिस्तान को अधिक स्थायित्व दे सके जैसे राष्ट्रीय एकता सरकार के द्वारा एक सर्वसम्मति नहीं बना पाना, ऐसे में सुरक्षा और तालिबान के साथ वार्ता प्रक्रिया जैसे गंभीर मुद्दों पर सहमति का अभाव। **आर्थिक समस्या** तो लगातार वैसी की वैसी ही बनी हुई है लगातार अभी भी बाह्य आर्थिक सहायता पर निर्भर है। 2014 के बाद जैसे सुरक्षा स्थितियों में आये परिवर्तन अपहरण और उसके बाद खतरनाक आतंकवादियों की मांग करने के रूप में सामने आया। ऐसे में तालिबानी शासन भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करने लगा। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का सहयोग लेकर आतंक के विरूद्ध युद्ध अभियान में अफगानिस्तान में "ऑपरेशन एंडयोरिंग फ्रीडम" चलाया जिसमें अलकायदा और तालिबान पर हमला किया गया। एक दशक तक चली लम्बी लड़ाई में अमेरिका ने काफी हद तक अलकायदा को तो खत्म कर दिया लेकिन तालिबान को नियंत्रित करने में असफल रहा ऐसे में भारत के समक्ष एक नया संकट उभरकर आता है कि अमेरिका की सैन्य वापसी के बाद भारत द्वारा 2004 से शुरू आर्थिक पुनर्निर्माण एवं सामाजिक विकास के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि तालिबान 2008 से भारत को लक्ष्य बनाकर भारतीय दूतावास और परियोजनाओं को निशाना बना रहा है। ऐसे में भारत के समक्ष विकल्प बहुत सीमित हो जाते है। भारत अमेरिका पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वह अफगानिस्तान में और अधिक समय तक रूके और सुरक्षा स्थिति को मजबूत करे तालिबान समर्थित क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण को बढाये वहीं अमेरिका भारत से लगातार मांग कर रहा कि भारत–अफगानिस्तान में अधिक भूमिका निभाये। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान में अधिक सकारात्मक भूमिका के कारण तालिबान मुखर रूप से उभर कर आया और काबुल की सत्ता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तालिबान राजनीतिक रूप से ज्यादा स्वीकार किया जाने लगा। जैसे रूस के साथ वार्ता, कतर में वार्ता काबुल सरकार के साथ वार्ता करना शामिल है।

अशांत अफगानिस्तान में शांति के योगदान में भारत का विकल्प महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक देश है यह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही वह अपने पड़ौसी देशों के साथ ऐसा कोई राजनीतिक व्यवहार करता है जिससे उसकी सम्प्रभुता को खतरा पहुंचे। भारत न तो 19वीं शताब्दी के अफगानिस्तान की परिस्थितियों और ब्रिटेन और रूसी साम्राज्यों के बीच चले ग्रेट गेम से अपने को दूर रखा और बींसवीं शताब्दी में सोवियत रूस के हस्तक्षेप के समय भी भारत ने अफगानिस्तान की सप्रभुता का सम्मान और सत्ता के समर्थन में अपना मत व्यक्त किया था लेकिन 1990 के बाद से परिस्थितियाँ बदली और अफगानिस्तान में गृहयुद्ध और बाद में पाक समर्थित तालिबान शासन का स्थापित होना भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं था क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारत त्रस्त था और अब तालिबान के सहयोग से और अधिक बल मिला। भारत ने कभी भी अफगानिस्तान के

RRIJM 2015, All Rights Reserved 

अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश नहीं की जिससे भारत के प्रति अफगान नागरिकों का भी सकारात्मक व्यवहार रहा है। भारत अफगानिस्तान में आर्थिक मदद को अधिक बढाना, सामरिक रूप से अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण इत्यादि कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक सहभागिता समझौता किया है। भारत को अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए अफगान सरकार की सहमति से तालिबान के साथ वार्ता करने की कोशिश करनी चाहिए इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत तालिबान की हिमायत करे या तालिबान को हम अफगानिस्तान में वैद्यता प्रदान करे। ऐसे गंभीर मुद्दों पर कूटनीतिक तरीके से हमें इनका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यही है कि जब तक पाकिस्तान का रूख अफगानिस्तान के प्रति नहीं बदलेगा तब तक अफगानिस्तान की समस्या का कोई हल नहीं होगा और पाकिस्तान के रूख में एक विशेष बात यह है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जबकि भारत अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता के दौरान भी भारत की भूमिका की प्रशंसा की और विकास कार्यों में अधिक योगदान और बढाने के लिए कहा। अर्थात् भारत अपनी और अधिक जिम्मेदारी बढ़ाये।

**अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने वाले प्रमुख बिन्दु –**

- अमेरिका को अपनी सैन्य वापसी की रणनीति पर पुनर्विचार करना।
- तालिबान के साथ वार्ता करना और इसे सतत् प्रक्रिया के साथ अधिक व्यापक रूप से आगे बढाना।
- छोटे–छोटे गतिरोध आने या तालिबान के हमलों के कारण शांति प्रक्रिया को नहीं रोकना ऐसा करने से तालिबान के हौसले अधिक बुंलद होते है।
- ट्रंप प्रशासन को अफगान नीति को स्थिरता और विश्वसनीयता के साथ लागू करनी होगी।
- भारत को अपनी भूमिका को अधिक जवाबदेहीता से निभाना होगा।
- पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान पर अमेरिका दबाव के साथ उसे तालिबान के साथ वार्ता के लिए दबाव डालना।
- चीन रूस और भारत को भी तालिबान के साथ वार्ता प्रक्रिया में भाग लेना।
- महाशक्तियों के प्रभुत्व से बचाने का प्रयास करना।
- दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के लिए, शांति व सौहर्द का वातावरण बनाने के लिए, सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महाशक्तियों के हस्तक्षेप से दूर रखने का प्रयास करना।
- अफगानिस्तान में स्थिर व मजबूत राष्ट्रीय सरकार का निर्माण आदि प्रयासों के द्वारा ही अशांत अफगानिस्तान में शांति का विकल्प ढूंढा जा सकता है।

## संदर्भ सूची


1. Despite US opposition, "Iran to be transport hub for north-South corridor" The Hindu 31 May, 2018
2. BBC Hindi News July 2019
3. Foreign Affair Minister Annul Report 2016-17
4. Foreign Affair Minister Annual Report 2017-18
5. Foreign Affair Minister Annual Report 2018-19
6. The Hindu July, 2019
7. Political Weekly Sep, 2017
8. Trump afghan Policy Statement, 2016
9. Foreign Affiar Minister Report Kabul, 2018


RRIJM 2015, All Rights Reserved 